भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2184

उत्तर देने की तारीख- 12.02.2026

असम में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

†2184. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) असम में स्वीकृत, कार्यशील और निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की जिला-वार संख्या कितनी है और उनमें कितना नामांकन हुआ है,

(ख) क्या शिक्षकों, अवसंरचना या मूलभूत सुविधाओं की कमी की सूचना मिली है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): असम में स्वीकृत, चालू और निर्माणाधीन ईएमआरएस की जिला-वार स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**स्वीकृत ईएमआरएस**	**क्रियाशील**	**निर्माणाधीन**
1	बक्सा	3	2	1
2	बारपेटा	1	1	-
3	धेमाजी	1	1	-
4	दीमा हसाओ	4	1	3
5	गोलपाड़ा	1	-	1
6	कामरूप	1	-	1
7	कार्बी आंगलोंग	3	1	1
8	कोकराझार	1	-	1
9	उदलगुड़ी	1	-	1
10	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	1	-	1
		17	**6**	**10**

कार्बी आंगलोंग जिले में एक ईएमआरएस का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन जनजातीय गौरव दिवस 2025 को किया गया। कक्षा VI से XII तक की कक्षाओं वाले सभी ईएमआरएस में 480 छात्रों की नामांकन क्षमता है।

(ख) और (ग): एनईएसटीएस ने ईएसएसई-2023 के माध्यम से 10391 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अपना पहला अभियान चलाया था और चयनित शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को विभिन्न ईएमआरएस में तैनात किया गया है। ईएसएसई-2025 के माध्यम से 7267 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। प्रत्यक्ष भर्ती के अतिरिक्त, एनईएसटीएस ने राज्य सरकारों को प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को नियुक्त करने की सलाह भी दी है। इसके अलावा, राज्य ईएमआरएस सोसाइटियों को रिक्त पदों के लिए आउटसोर्सिंग/स्थानीय नियोजन के आधार पर अतिथि शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नियोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि शैक्षणिक गतिविधियां बाधित न हों।

ईएमआरएस में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि:

i) नए ईएमआरएस भवनों के लिए मानकीकृत डिजाइन विकसित किए गए हैं, जो आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं, छात्रावासों, स्टाफ क्वार्टरों और खेल अवसंरचना को सुनिश्चित करते हैं।

ii) अनुच्छेद 275 (1) के तहत स्वीकृत पुराने ईएमआरएस के उन्नयन के लिए ₹ 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

iii) कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय-पक्ष निरीक्षणों (आईआईटी, एनआईटी, सीबीआरआई, आदि) और संयुक्त समीक्षाओं के माध्यम से नियमित निगरानी की जाती है।

****